ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का स्थापित किया जाना

483. **श्री राम नरेश यादव :**

श्री राम जठमलानी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत फल तथा सब्जी उत्पादक देशों में विश्व में दूसरे स्थान पर है ;

(ख) यदि हां, तो देश में फलों तथा सब्जियों का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपयोग न किए जाने के कारण कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत भाग बेकार चला जाता है ; और

(घ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इन उत्पादनों पर आधारित कुटीर उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमान है कि देश में हर वर्ष लगभग 230 लाख मीटरी टन फलों और 430 लाख मीटरी टन सब्जियों का उत्पादन होता है।

(ग) अनुमान है कि फलों और सब्जियों के उत्पादन के लगभग 35 प्रतिशत का उपयोग नहीं होता है ।

(घ) राज्य और केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से स्थानीय उपलब्ध फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों तथा सहकारी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इनके अलावा, इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन शुल्क में रियायत और वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

Ceiling on Wheat Stock

484. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:

SHRIMATI RATAN KUMARI:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government has asked the States to impose a ceiling on wheat stocks to prevent the possibility of hoarding by traders;

(b) if so, the details of the guidelines issued in this connection;

(c) whether due to hoarding of foodgrains by traders, the price of foodgrains in open market goes up; and

(d) if so, what action Government propose to take against the traders found indulging in hoarding foodgrains/wheat more than the permissible limit of stock?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) Yes, Sir.

(b) The State Governments were advised to impose stock limits wherever and to the extent necessary.

(c) Hoarding of foodgrains by traders could create a scarcity in the open market and prices in the open market could go up as a consequence.

(d) The State Governments are already empowered to take action against traders holding foodgrains in excess of the prescribed quantities.

Import of Hot Rolled Coils

485. SHRI SUNIL BASU RAY:

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) by when Steel Authority of India units be able to meet the internal requirements of hot rolled coils and import will be stopped; and